

यूपी में शुगर प्रॉडक्शन बढ़ने से गहापात्र की चीनी मिलों का बिजनेस झटक सकता है उत्तर प्रदेश

कुछ राज्यों में महाराष्ट्र की चीनी मिलों का बिजनेस झटक सकता है उत्तर प्रदेश

[जयश्री भोसले | पुणे]

महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री अधिक प्रॉडक्शन से वृत्त मै है। उसने उत्तर प्रदेश में अपना पांचरिक घोटा बाजार भी गवा दिया है। राज्य में प्रॉडक्शन पिछले साल के दिकोर्ड लेवल की तरफ बढ़ रहा है, इससे यूपी सहित कुछ दूसरे राज्यों में खुद को बचाने के लिए एक्सपोर्ट मार्केट का रुख कर रही है। शुगर इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में शुगर प्रॉडक्शन पिछले साल के रिकॉर्ड लेवल की तरफ बढ़ रहा है।

ऐसे में यूपी सहित कुछ दूसरे राज्यों में महाराष्ट्र में चीनी की सलाहू रुक जाएगी, जिससे वहाँ की चीनी मिलों की आर्थिक हालत खराब हो सकती है। पिछले तीन साल में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन के समान में देश में नबर वन परिषिक्षण पर पहुंच गया था। महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव शुगर फैब्रिरिज फैब्रिरिज के मैरीजिंग डायरेक्टर संजय काथल ने कहा, 'उत्तर-पूर्वी और उत्तर भारत में यूपी ने हमारे कारोबार पर कज्जा कर दिया है। इसलिए हमारी शुगर

लगेठी चपत

- उत्तर प्रदेश में शुगर प्रॉडक्शन पिछले साल के दिकोर्ड लेवल की तरफ बढ़ रहा है, इससे यूपी सहित कुछ दूसरे राज्यों में गहापात्र की खपत करता है। राज्य का 2017-18 में शुगर प्रॉडक्शन 107 लाख टन्नल रहा था और मौजूदा सीजन में उसके पास 96.5 लाख टन्नल का स्टॉक है।

प्रदेश से दूसरे के जरिए जो शुगर मिल रही है, उनके बीच महाराष्ट्र की मिलों से दूसरे के जरिए भूजी जानी वाली शुगर के बारों के मुकाबले गुणवत्ता में तेहतर है। महाराष्ट्र अकेले ही करीब 24-25 लाख टन्नल शुगर की खपत करता है। राज्य का 2017-18 में शुगर प्रॉडक्शन 107 लाख टन्नल रहा था और मौजूदा सिजन में प्रदेश का स्टॉक है। संजय ने कहा, 'यह बहुत नियंत्रित है कि हम महाराष्ट्र में शुगर प्रॉडक्शन को कैसे नियंत्रित करें, जो देश में अकेले ही अधिक सलाहू से जड़ रहा है। हमें शुगर एक्सपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।' राज्य की मिलों को गन्ना किसानों का काफी बकाया उकाना है। इस महाने गन्ने में एक और निजी चानी मिल शुरू होने जा रही है, जिससे मिलों की संख्या बढ़कर 194 हो जाएगी। वहीं, गन्ने सरकार आशिक तरीं में फर्मी कुछ चीनी मिलों को रिवाइव करने की भी कोशिश कर रही है।



Economic Times

18/3/2019

✓ ✓